

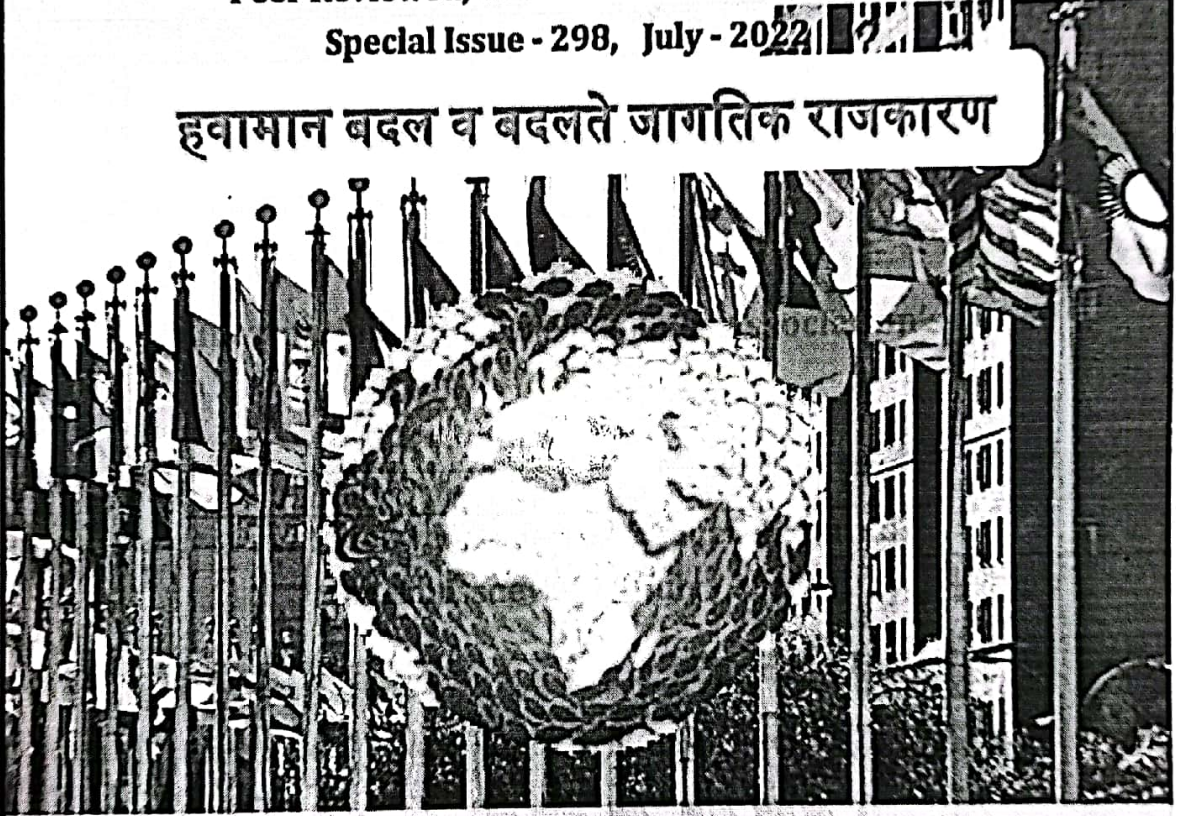
International Research Fellows Association's
RESEARCH JOURNEY

International E-Research Journal

Peer Reviewed, Referred & Indexed Journal

Special Issue - 298, July - 2022

हवामान बदल व बदलते जागतिक राजकारण



विशेषांक संपादक :

संदीप तुंडूरवार

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

श्री विज्ञानी नगर महाविद्यालय, नागपूर.

डॉ. विनोद गायकवाड

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

ग.मि. सुरारका कला व वाणिज्य महाविद्यालय,

क्षेगाव, जि. बुलढाणा.

डॉ. शरद सांबारे,

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

यशोवा गर्लर्स अ‍ॅन्ड्स, कॉमर्स कॉलेज, नागपूर.

विशेषांक सहसंपादक

डॉ. विनकर चौधरी

डॉ. अमर बोधरे

डॉ. बाळासाहेब जोगवंड

डॉ. संतोष डाखरे

डॉ. भास्कर वघाळे

मुख्य संपादक :

डॉ. धनराज धनगर



For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS



INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S
RESEARCH JOURNEY

International E-Research Journal

Peer Reviewed, Referred & Indexed Journal

Issue - 298

विशेषांक संपादक :

संदीप तुंडूरवार

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर .

डॉ. विनोद गायकवाड

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

ग.भि. मुरारका कला व वाणिज्य महाविद्यालय,

शेगाव, जि. बुलढाणा.

डॉ. शरद सांबारे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

यशोदा गर्ल्स ऑर्टस, कॉमर्स कॉलेज, नागपूर.

विशेषांक सहसंपादक

डॉ. दिनकर चौधरी

डॉ. अमर बोंदरे

डॉ. बाळासाहेब जोगदंड

डॉ. संतोष डाखरे

डॉ. भास्कर वघाळे

मुख्य संपादक :

डॉ. धनराज धनगर

SWATIDHAN INTERNATIONAL PUBLICATIONS

For Details Visit To : www.researchjourney.net

*Cover Photo (Source) : Internet.

© All rights reserved with the authors & publisher

Price : Rs. 1000/-

Published by -

© Mrs. Swati Dhanraj Sonawane, Director, Swatidhan International Publication, Yeola, Nashik

Email : swatidhanrajs@gmail.com Website : www.researchjourney.net Mobile : 9665398258

INDEX

No.	Title of the Paper	Author's Name	Page No.
01	मागास आणि अविकसित देशातील पर्यावरण विषयक प्रश्न	डॉ. संजय गव्हाणे	07
02	मानवी पर्यावरणासमोरील प्रश्न, आव्हाने, पर्याय	डॉ. रमेश चौधरी	10
03	आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भारत	प्रा. गोपालकृष्ण राखोंडे, डॉ. प्रतिभा टावरी	15
04	पर्यावरण संरक्षण व भारत	डॉ. प्रतिभा गडवे (दातीर)	19
05	मागास आणि अविकसित देशातील पर्यावरण विषयक प्रश्न	डॉ. नागेश्वर कन्होळे	25
06	मानवी पर्यावरणासमोरील प्रश्न, आव्हाने, व पर्याय	डॉ. अजय बोरकर	29
07	आंतरराष्ट्रीय पटलावरिल उथल - पुथल व भारताचे स्थान	डॉ. जीवन पवार, रुपसिंग राठोड	35
08	हवामान बदलासंदर्भातील जागतिक विचारांची मांडणी व भूमिका	डॉ. नंदाजी सातपुते	40
09	पर्यावरण संरक्षणार्थ बड्या राष्ट्रांची भूमिका आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रयत्न	डॉ. लक्ष्मण शिराळे	45
10	मानवी पर्यावरणा समोरील प्रश्न, आव्हाने आणि पर्याय	डॉ. किशोर कुडे	54
11	बदलत्या हवामानाचा मानव जातीवर होणारा परिणाम व जागतिक राजकारण	डॉ. प्रिया बोचे	59
12	शाश्वत विकास संकल्पना : स्वरूप आणि आव्हाने	डॉ. रिता धांडेकर, डॉ. श्रीकांत शेंडे	63
13	पर्यावरण व आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका : एक चिकित्सक अध्ययन	डॉ. सुभाष उपाते	70
14	मानवी पर्यावरणा समोरील प्रश्न, आव्हाने व पर्याय	डॉ. बबिता येवले	77
15	महाविद्यालयीन ग्रंथालयात माहिती साक्षरता काळाची गरज	प्रा. उमेश गावंडे	81
16	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची जागतिक पर्यावरण विषयक भूमिका	वि. पा. करणकार	84
17	लोककल्याणकारी योजनेतून पर्यावरण संरक्षण	डॉ. भास्कर वघाळे, डॉ. रायन महाजन	90
18	पर्यावरणाच्या संदर्भात प्रत्येक राष्ट्राची धोरणे निर्णय व कृती	सचिन ढोले, प्रविण दुधारे	94
19	जागतिक महासत्ता आणि वैश्विक धुवीकरण	पौर्णीमा मेश्राम	97
20	A Study of Global Climate Change	Dr. Akash Bangar	101
21	Climate Change and Analysis of Political Economy and Impact on India	Dr. Ravindra Bhanage	107
22	वृद्ध परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन	प्रा. किशोर नैताम, डॉ. शरद सांबारे, डॉ. संगीता सोमवंशी	117
23	विश्व राजनीती के बदलते संदर्भ बिंदू	संदीप तुंडरवार	123

Our Editors have reviewed papers with experts' committee, and they have checked the papers on their level best to stop furtive literature. Except it, the respective authors of the papers are responsible for originality of the papers and intensive thoughts in the papers. Nobody can republish these papers without pre-permitssion of the publisher.

• Chief & Executive Editor

विश्व राजनीति के बदलते संदर्भ बिंदु**संदीप तुंदूरवार****राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख, श्री विज्ञाणी नगर महाविद्यालय, नागपुर.****सारांश**

'द ईकानामिस्ट टाइम्स' के अपने लेख में नामांकित वैश्विक राजनीतिक विचारवंत एडवर्ड लॅटवाक ने कोरोना पश्चात वैश्विक राजनीति अपनी करवट बदलेगी यह भाष्य किया था. विश्वभर में कोरोना ने जो हडकंप मचाया था उसका असर सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर होने वाला नहीं था. उसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, लष्कर इस पर होने वाला है. यह वर्तमान में छिडे हुये रशिया-युक्रेन के विवाद से स्पष्ट होता है. कोव्दिड काल में इस्त्रायल-गाझापट्टी का विवाद, अफगाणिस्तान पर तालिबानीयों का अंकुश, वहां के लोकनिर्वाचित शासन का अपदस्थ होना, साथसाथ अफगाण क्षेत्र में पैदा हुई पेचिदा परिस्थिती जो स्थानिय लोगों के मानवीयता को बुरी तरह नामशेष करने वाली है. भारत-चीन में लद्दाख, गलवान में हुई लष्करी झड़पे, डोकलाम के क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप, अरुणाचल प्रांत के निकट लष्करी व्यवस्था की एकजूट तथा लष्करी बंकरों का निर्माण चीन की साम्राज्यवाद विस्तारवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है. ईस्त्रालय-पॅलेस्टाईन में उभरा नया विवाद, इराण पर अमेरिका का शिकंजा कसना उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में पैदा हुआ तणाव, उत्तर कोरिया द्वारा युनो को नजर अंदाज करते हुए अण्वस्त्रों का परीक्षण, यस सभी घटनाये वैश्विक राजनीति में भूचाल मचाने वाली घटनाए साबीत हो सकती है इसी परिदृश्य में विश्व की राजनीति में गरमागरमी या स्थायी संबंधों में बदलाव आ रहा है. क्षी जिनपिंग, व्लादीमीर पुतीन द्वारा अपने-अपने देशों के विधिमंडल से पारित प्रस्ताव के तहत २०३६ तक पदासीन रहने को स्वीकृता को देखते हुए विस्तारवाद तथा उससे पणपणे वाली युद्ध व्यवस्था सामने आती है.

कोव्दिड के पूर्व विश्व की राजनीति २०२० में गरमागरमी के चरमसीमा पर पहुँची थी. जिसमें इराण के अण्वस्त्रों को लेकर युद्ध की आशंका जताई गई थी वह पीछे रही और सारा विश्व कोव्दिड से पैदा हुयी महामारी पर क़ाम करने लगा. यह भी देखा गया की विश्वभर के मानवीयता पर जो संकट उभरा था उसे बिना किसी विरोध के निपटा जाये, शुरूवाती दौर उत्साहवर्धक रहा. युरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इन राष्ट्रों ने साथ मिलकर कोव्दिड के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रतिबंधात्मक व्यवस्था की पहल की. अमेरिका ने अपने जीडीपी का २१ प्रतिशत, जपान २७ प्रतिशत, जर्मनी १३ प्रतिशत, इंग्लैंड ने १७ प्रतिशत उसपर खर्चा किया तथा अपने जनव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया. अमेरिका ने दो राजनीतिक मुद्दों पर क़ाम किया एक चीन पर कोव्दिड के जरिये जैविक अस्त्र का इस्तमाल करने का आरोप लगाते हुए युरोप, आशिया, आफ्रिका देशों से उसकी हिस्सेदारी कम हो इस पर राजनीति गतिविधिया को केंद्रित कर चीनी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया. दुसरा, चीन के आर्थिक एवं राजनीतिक विस्तारवाद पर अंकुश लाने के लिए हिंद महासागर में 'क्वाड' नामक संगठन का निर्माण किया. जिसमें भारत, जपान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ सहभागी है. गलवाण, डोकलाम की घटना के बाद भारत ने ब्रिक्स को कमजोर करने की शुरुवात करते हुए साथ में रशिया से घनिष्ठता बडा दी. आशिया के सत्ता संतुलन को हमेशा चीन ने अपनी तरफ से परेदी करते हुए असंतुलित बनाने का प्रयास किया है. १९४८ के बाद चीन अपनी प्राचीन युद्धनीती के साथ कृति को अंजाम देता आ रहा है. चीन का सुप्रसिद्ध सेनानायक सन त्सु जो ईसापूर्व ६०० शताब्दी में हुआ था. उसने युद्ध की अपनी एक नीती रखी 'सशस्त्र या खुला युद्ध के बजाय शत्रु को

पराजित करना सर्वोत्तम है, अज्ञानी लोग युद्ध करते हैं, लेकिन ज्ञानवंत सशस्त्र युद्ध के बिना विजय हासिल करते हैं। चीन का १९६२ में भारत के साथ जो सशस्त्र संघर्ष हुआ उसके पश्चात उसने सन १९६२ की रणनीति को अंमल में लाया। चीन वर्तमान में दंग के २४ शब्दों के सुत्रावली को विस्तारवाद का जर्जिया बना रहा है। 'दूर रहकर विश्व का निरीक्षण करो, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखो, अपने देश में शांति बनाकर सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन कर क्षमताओंको बढ़ाओ और शांति के दौरान मिले हुए समय का सदुपयोग करो' चीन ने लगातार इस सूत्र पर चलते हुए खुदको विश्व के दूसरे विकसित तथा समृद्ध अर्थव्यवस्था के पायदान पर अपना स्थान बनाया। १९६१ में विश्व के द्विध्रुविकरण की व्यवस्था समाप्त हो कर विश्व का सत्ता संतुलन धराशायी हुआ था उसे पुनर्जीवित कर रशिया के स्थान पर चीन ने अपनी जगह बनायी। लेकिन चीन की चुनौतीया अमेरिका जैसे ही बरकरार है। क्योकी अमेरिका की 'दरोगा' नीति चीन चाहता है। लेकिन दोनों के वर्तनशैली में गहरा अंतर है। अमेरिका की राजनीतिक चाल चरित्र पर जनता, व्हिसल ब्लाउ, लोकतंत्रात्मक संस्था, समाचार जगत, बुद्धिवंत वर्ग, पुंजीपती, न्यायव्यवस्था इनका नियंत्रण है। ट्रम्प के सर्वाधिकारवाद को रोकने में यह अलग अलग घटक महत्वपूर्ण रहे।

लेकिन चीन में इस तरह की पर्यायी व्यवस्था नहीं है। पुतीनकालीन रशिया में भी वह नहीं है इसी वजह संघर्ष का केंद्रबिंदू आशिया से सटकता हुआ युरोप केंद्र बन गया। रशिया-चीन-पाकिस्तान का एक साथ होना या पुतीन के भाषा में अपने स्वर को मिलाकर विश्व को संकेत देना यह कोव्हिड पश्चात बदलते वैश्विक राजनीति का एक नया चेहरा है। चीन पर कोव्हिड से संबंधित संदिग्ध आरोप है। इस परिस्थिती से बाहर निकलने का मोका चीन को मिला है। तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोर्चा निर्माण करने की एक आशा किरण दिखाई दे रही है। नाटो संगठन इस आकृतीबंध को नजर अंदाज नहीं कर सकता इसीलिए वह मौखिक दबाव बनाये रखा है। रशिया-युक्रेन विवाद में कोई बड़ी रंजीश नहीं होते हुए भी रशिया का युक्रेन पर आक्रमण विश्व के मानचित्र में होनेवाले बदलाव का प्रारंभ है। भारत ने युनो में तिन्ही बार तटस्थता का निर्णय लिया वह वर्तमान दौर में सबसे सटीक निर्णय था। इस निर्णय से भारत के प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू की विदेशनीती पर मुहर लगी। हमने हमारी तटस्थता को त्यागना यह चीन या पाकिस्तान के विस्तारवाद को समर्थन देना इसका यह सूचन बन जाता। विश्व के सामर्थ्यशाली देशों का आकलन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 'बढ़ती क्षमता के साथ उत्तरदायित्व का भी भान होना चाहिये, खुद को शक्तिमान मानने वाले राष्ट्र हमेशा भयगंड से ज्यादा आहत रहते हैं'। कोव्हिड के पश्चात बदलती वैश्विक राजनीति अपने भय में फसी हुई है और उसपर जवाबदेही, मानवीय सभ्यता के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। जैविक अस्त्रों से लेकर आण्विक अस्त्रों तक का रास्ता मानवीय सभ्यता पर एक गहरे संकट के रूप में खड़ा है।

बीजशब्द - बदलती वैश्विक स्थिती, बड़े राष्ट्रों की भूमिका, बदलते संदर्भ .

विषय प्रारंभ

शुद्धाती दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा को स्वतंत्र पहचान देने वाले मॉर्गेंथा एवं थॉम्पसन ने शायद यह नहीं सोचा होगा की 'महामारी' की वजह से वैश्विक राजनीति का रूख बदलकर विश्व भर में कोहराम मचा सकता है। उनके समकाल में परमाणु अस्त्र तथा जैविक अस्त्रों की बात भी चल रही थी और परमाणु अस्त्र का गहरा असर भी दिखाई दिया। विश्व विश्व भर की राज्यव्यवस्थाएं कुछ देर के लिए भयप्रद अवस्था में घली गई थी और मानव अस्तित्व का संकट पैदा हुआ था। ऐसी आशंकाएं जोर पकड़ने लगीं।

लेकिन उस तुलना में कोविड पछात विश्व की राजनीतिक उथल-पुथल ज्यादा ही गंभीर एवं टकराओ पर अंकुश लाने में समर्थ नेतृत्व का अभाव यह पेचीदा रिथति बनी हुई है. साधारण तौर पर माना जाता है की वैश्विक राजनीति को आयाम देने वाले कालखंड का वर्गीकरण उस वक्त की संस्थात्मक गतिविधियों पर आका गया जैसे पहला काल खंड प्रथम विश्वयुद्ध का, दूसरा १९२० से १९३९, तीसरा कालखंड १९३९ से १९४५, चवथा द्वितीय महायुद्ध के समाप्ति से लेकर एक धृवीय व्यवस्था के निर्माण तक. पांचवा, १९९१ से २००१ तक एक धृवीय व्यवस्था से आक्रमक आतंकवाद तक, छटा २००१ से २०१९ तक जो विश्वमर में फैले आतंकवाद के समाप्ति का भरकस प्रयास साथ हरित विश्व की व्यवस्था यहां तक कहा गया. लेकिन सातवा कालखंड जो मर्यादित लेकिन सबसे असरदार रहा वह २०१९ से २०२२ के प्रारंभ तक का है. कोविड-१९ नामक विषाणु का विश्वभर फैलाव तथा जिम्मेदारी तय करने की भूमिका पर गहरा संदेह जताते हुए आर्थिक धृवीकरण पर विश्व को दो फाको में बांटने की सभी राष्ट्रों की स्तरीकृत राजनीति ने कोविड पश्चात वैश्विक राजनीति के सभी संदर्भ पर नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य किया इसी का परिणाम वर्तमान युद्धव्यवस्था पर दिखाई देता है.

लिओ डॉलस्टाय ने कहा था 'जब आपसी मनमूटाव पर नियंत्रण लाना मुश्किल होता है, तब दूसरों पर आक्रमणों की बौछार कर लक्ष्य को भटकाया जाता है'. परिणामस्वरूप सत्तासंतुलन खोकर साम्राज्यवादी व्यवस्था का निर्माण होता है. कोविड काल के दौरान विश्वभर में जो भी ताण-तणाव निर्माण हुए वा कराए गए उसके पीछे का मकसद विश्व के मानचित्रों को बदलाते हुए सामुहिक सुरक्षितता वाली प्रभावी संगठनों को कमजोर किया जाए. कोविड काल में WHO ने अपनी विश्वसनीयता खो दी परिणामस्वरूप WHO के अध्यक्ष के बयानों से सभी देशों ने अनदेखा किया अमेरिका ने से बाहर होते हुए उसकी वार्षिक सहायता अनुदान ठप्प करवाया. डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए के अध्यक्ष चीन की भाषा बोल रहे हैं ऐसी टिप्पणी की, इससे अमेरिका-चीन के संबंधों में दरारें आईं और वर्तमान समय में वह ज्यादा गहरी असरदार बन रही है इसका मासलेवाईक उदाहरण अफगाणीस्तान में तालिबान राजवट को चीन द्वारा विश्व में सबसे प्रथम अनुमोदन देना और उसकी पैरवी करते हुए तालिबान व्यवस्था को अफगानिस्तान की अधिकृत व्यवस्था बताना यह कोविड पश्चात विश्व की बदलती राजनीति का एक अहम उदाहरण है.

करोना काल का विश्व

करोना ने विश्व के अर्थ चक्र पर सबसे ज्यादा प्रहार किया विश्व की उत्पत्ति से लेकर आज तक के महामारी पर इस दौरान बहस हुयी उस पर लंबी मँराधान चली। कुछ बातों को सामने रखा भी गया करोना का सबसे बुरा असर यूरोप, अमेरिका इस श्वेताई राष्ट्रों पर ज्यादा हुवा और उनकी अर्थव्यवस्थाएं जायबंदी के घपेटो में आयी. सबसे कम असर आफ्रीकन देशों पर हुवा लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गयी और बड़े हद तक चोट पहुची. भारत-चीन पर असर होगा लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएं वापसी करेगी, चीन का जीडीपी तेजी से १० प्रतिशत के उप्पर गया तो भारत ६.१ प्रतिशत रखेगा ऐसा कयास अर्थ क्षेत्र में है. लेकिन पारंपारिक बड़े राष्ट्रों को बड़ा झटका लगा और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी सकल राशी का २५ प्रतिशत हिस्सा लोगों पर खर्च करना पड़ा। प्रख्यात साहित्यिक एमोली वेबने इस पर थोड़ा सा हटकर अपना विचार रखा और उन्होंने कहा अगरिका फी G-MAFIA तथा चीन की BAT इन कंपनियों को बैशुमार मुनाफा मिलने वाला है. जो तंत्रज्ञान एवं आपके दरवाजे तक दरवाजे तक सुविधा देने वाली यह कंपनियां हैं. Amazon कंपनी ने कोरोना काल में अबतक का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया

जिससे २० बढ़ोतरी वृद्धी हुई। यह एक उदाहरण है एक मिसाल के तौरपर अगर लेते हैं तो महामारी पूंजीवादी व्यवस्था को सबसे ज्यादा फायदेमंद रही, लेकिन राष्ट्र के तौरपर सोचते हैं तो अमेरिका जैसे देश पर उसका बुरा असर हुआ। चीन अपनी पोलादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है इसलिए वहां पर क्या हो रहा है इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, हेन्री किंसीगर एवं अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन ने भी यह बात मानी थी 'चीन के चरित्र का पता लगाना मुश्किल है' जिस वुहान शहर के 'बाँयलॉजिकल लैब' से यह विषाणु सारे विश्वभर फैला, यह पाश्चात्य राष्ट्र तथा भारत के बख्शी लोग मानते हैं, वहीं पर २०१८ में श्री. जिनीपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्तालाप के लिए बुलाया था। महज ८ महीने बाद विश्व भर में खलबली मचाने वाली वह बात सामने आयी। चीन के वुहान और इटली के मिलान में गहरे आर्थिक व्यवहार से थे कोविड के वजह वुहान जितना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ उतना मिलान हुआ। मार्च २०२० मिलान में ५५ हजार लोगों को उनके रिश्तेदारों ने खो दिया पूरा इटली क्षतिग्रस्त हुआ वहां की आरोग्य व्यवस्था जमीनदोस्त हो गयी। अर्थव्यवस्था का पिछाडना सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था पर हल्ला बोल होता है। और यही बात यूरोप, अमेरिका, अहस्ट्रेलिया, भारत ने अनुभव की कोविड चरमसीमा पर था तब चीन ने अपनी साम्राज्यवाद नीति को और आगे बढ़ाया। व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, जापान, ताईवान, भारत इनके साथ सीमावाद की पुरानी जख्मों को उजागर कर इन राष्ट्रों के प्राधान्य क्रम बदल दिए। व्हिएतनाम के पास कृत्रीम बेटों का निर्माण कर उस पर अपनी संरक्षण सिध्दता बनाना पूर्वी आशिया के मानचित्रों में बदलाव की राजनीति थी। अपनी आरोग्य व्यवस्था की हालात ठीक करने के बजाय लष्करी व्यवस्था का मार्ग अपनाना यह विश्वशांती के खिलाफ तथा सत्तासंतुलन के विपरीत था जो चीन, रशिया और अमेरिका ने भी किया। रशियाने बेलारुस, जार्जिया के संदर्भ में किया। अमेरिका ने ईरान के संदर्भ में यही बात दोहराई। विश्व के कद्दावर राष्ट्रों पर परमाणुअस्त्र या महामारीअस्त्र का असर नहीं होता है यह पुनश्च एक बार प्रतीत हुआ। विंसी राइट का सत्ता संतुलन के संदर्भ में कहना था 'सत्तासंतुलन सर्वसामान्य सामाजिक सिध्दांतों का प्रगटीकरण करते हैं' लेकिन सिध्दांत निर्मिती के बजाय विश्व के दरोगा मानने वाले राष्ट्रों ने अपनी साम्राज्यवादी अभिलाषा को ज्यादा प्रचारित कर उसका विश्व पटल पर प्रदर्शन किया।

विश्व राजनीति के बदलते संदर्भ बिंदु

कोविड के पश्चात वैश्विक राजनीतिक के संदर्भ बिंदु बदल रहे हैं। यह बदलती वास्तवता नए नेतृत्व या सत्ताओंके परिवर्तन से नहीं आयी बल्कि पुतिन, शि. जीनीपिंग, नरेंद्र मोदी, बोरिस जहन्सन, जस्टिन ट्रुडो। इनकी मौजूदगी में विगत कुछ वर्षों से है। अपवाद डोनाल्ड ट्रंप का है लेकिन यह दौर अगर तौलनिक स्तर पर देखा जाए तो द्वितीय विश्वमहायुद्ध कालीन का है, जिसमें फ्रैंको, मुसोलिनी, हिटलर, स्टैलीन, कत्सुरा तारो का समावेश था। वर्तमान संदर्भ के नेतृत्व में वह छबी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। परिणामस्वरूप वैश्विक राजनीति में हावी होने के लिए लगातार जो संघर्ष दिखाई देता है वह राष्ट्र का कम नेतृत्व की छबी ज्यादा है इतिहास से क्या स्मरण किया जाए इस पर वैश्विक राजनीति नहीं चलती लेकिन इतिहास में नाम दर्ज हो इसपर उनकी कार्यकर्तृत्वता बताई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने यह अनुभव किया और बड़ी बात परोक्ष और अपरोक्ष सामने आती है .

कोविड को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जिसका भारत भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जो संदर्भ बिंदु बवला वह रोजगार क्षमता, शांतता तथा स्थैर्य, मानवी अभ्युदयता की पैरवी, हरित विश्व निर्मिती का प्रयास, कार्बन ऊत्सर्जन तथा पर्यावरण सुरक्षितता, लोकतंत्रात्मक

व्यवस्था की पहल, आंतकवादी संगठनों पर नियंत्रण तथा आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश, संसाधनों का समानविवरण तथा हिरसोदारी यह कोविडपूर्वकालीन मुद्दे संघर्ष बिंदू कहे जाते थे. लेकिन कोविड पश्चात संदर्भ बिंदू चीनी अर्थव्यवस्था तथा विस्तारवाद पर लगाम लगाना, नाटो का परिण विस्तार बनाना, चीनीव्यवस्था विरोधी राष्ट्रों की लागूबंदी, चीन-रशिया गानशिकता पर वर्षस्य प्रस्थापित करना यह यनी है.

अमरिका ने 'इराण' संघर्ष का बिंदू बदलते हुए 'चीनी' केंद्रित रचना पर कायम किया. डोनाल्ड ट्रम्प की या कहे तो अमरिका की विदेशनीती भूमिका को न बदलते हुए सामायिक प्रतिरूपों के तौर पर चीन के खिलाफ वैश्विक वातावरण बनाना शुरू किया. अमरिका और चीन में 9000 अरब डल्लर्स का व्यवहार है साथ में 29 मिलीयन डल्लर्स का चीनी बोझ अमरिका पर है इसीलिए चीन के साथ सीधा संघर्ष नहीं करता. वैश्विक राजनीति में हमेशा 'तेल' का मुद्दा सामने रखा जाता है और उसे केंद्रित कर अपने अपने खेमों का निर्माण किया जाता है. लेकिन चीन में तेल उत्पाद विश्व की तुलना में 3: है. फिर भी चीन की उपयुक्तता नदारद नहीं की जाती क्योंकि चीन की दो बातों की सुविधा विश्वभर के पुंजीपतियों के लिए अधिक मुनाफे वाली है. एक, कम वेतन में अधिक उत्पाद और दूसरा जीवनोपयोगी उत्पादक का सबसे जादा भंडार. इसमें बिजली, कोयला, पाणी, लोहा, सिमेंट, दवाईया इ. का समावेश है. भारत दवाईके बारेमें चीन पर निर्भर है चीन से 20: युकेन से 20: कच्चा माल भारत आयात करता है. यही नहीं सबसे बड़ी मुर्तीका निर्माण चीन से किया गया है इस वास्तववाद को देखे तो चीन की अर्थव्यवस्था पर युरोप अमेरिका या भारत अपना प्रभुत्व प्रस्थापित क्यू नहीं कर सकता यह स्पष्ट होता है. कोविड पूर्व काल में चीन ने 'रोड अॅन्ड बेल्ट इनोवेटिव्ह' नामक भव्यदिव्य प्रकल्प बनाते हुए विश्व के 85 देशों को सीधा जोड़ने का प्रयास शुरू किया उससे अमरिका एवं अन्य राष्ट्रों में हडकंप मच गया. कोविड के काल में चीनी अर्थव्यवस्था खोकली हुयी ऐसा विश्वभर माना गया मात्र 29 ट्रिलीयन की अर्थव्यवस्था रखनेवाला चीन अब भी विस्तारवाद की रणनीती क्यू अपनाता है यह स्पष्ट होता है. रशिया द्वारा तो युकेन पर हुए हमले का खुला समर्थन चीन, तुर्कस्तान ने किया तो, जर्मनीने विरोध जताने के लिए स्पष्ट नकार दिया. रशिया के युकेन पर आक्रमण ने संदर्भ बिंदू को बदल दिया. इराण, तुर्कस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव रशिया के साथ में हो गये. अफगाणिस्तान में तालिबान राजवट को सबसे पहले चीनने संमती देकर आशिया के सत्तासंतुलन को नये उभरते केंद्र के रूप में खुदको वैश्विकपटल पर रखा उसकी रणनीती वैश्विक राजनीति को अलग आयाम देने वाली है. तैवान, दक्षिण कोरिया, मंगोल, नेपाल, नेफ्रा, तिबेट की सीमाएं चीन की सीमातर्गत हो इस का प्रयास वैश्विक राजनीति की करवट बदलने वाली साबीत होगी. कोविड के मार से चीन बेहाल है इस तरह की बातें चीन के विस्तारवाद पर असर नहीं करती. एक फर्क अमरिका एवं चीन-रशिया के संदर्भ में समझना चाहिये. अमरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने सीमा को नियंत्रित करते हुए दुसरे मुल्कोपर आधिपत्य बनाये रखा और उसका जरीया नाटो, सितो, सेंटो, जी-9, जी-20, जी-29, जी-85, आर्कुस, क्वाड, दक्षिण आशिया संगठन को बनाया. मात्र चीन-रशिया छोटे संगठन के माध्यम से अपने उपस्थिती दर्शाता है और विस्तारवाद की रणनीती अपनाता है, उनकी विदेशनीती की परिभाषा वही है. इसलिये विश्व की व्यवस्था के सामने जो संकट है व तेल का नहीं बल्कि विस्तारवाद का है. यही संदर्भ बिंदू कोविड के पश्चात बना हुआ है.

गुटो का निर्माण या बड़े राष्ट्रों का संगठन इनसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को हमेशा प्रभावी किया गया है. सम्बंधों में अनिवार्यता को सामने रख कर सोचा जाता है खासकर आर्थिक एवं लष्करी सहायता के बारे में! अफगानिस्तान, चीन युकेन यहा के राजनीतिक हालातों का सिधा प्रभाव भारत असरसदार रहा

परिणामस्वरूप भारत को भी ज्यादा न ताणते हुए संबंध बरकरार रखने का प्रयास करना पडा. क्विन्सी राईट इसका दुसरा पैलू सामने रखते हुये कहते है 'दुसरे वेशो मे संप्रगुता कायम रखने की इच्छा रखनेवाले बडे राष्ट्र सत्तासंतुलन की फिक्र न करते अपना रख तयार करते है' भारत के माजी परराष्ट्र सचिव जे एन. दीक्षित भारत की विदेशनीति मे कहते है 'भारत की विदेशनीति ने हमेशा विस्तारवाद को विरोध जताते हुए उच्च नैतिक व्यवस्था आधारित विदेशनीती की पहल की है'¹ वर्तमान में यह बात चेष्टा का विषय बनी हुई है फिर भी इस विदेशनीति की सराहना युनो ने की संदर्भ विंदू बदलते रहे है लेकिन उच्चतम मानदंड की व्यवस्था भी जरूरी समझी जाती है.

बदलती वैश्विक राजनीति के संदर्भ मे भारत का दृष्टिकोन

१९५० से लेकर २०१४ तक भारत की विदेश नीति संविधान मे अंतर्गत अनुच्छेद ५१ मे समाविष्ट मूल्यो पर चलती रही. अलग अलग विचारधाराओकी १५ सरकारे रही है लेकिन विदेशनीती का मूलस्रोत नहीं बदला. २०१४ मे नरेंद्र मोदी की सरकार स्थापित होने के बाद वैश्विक राजनीति के संदर्भ मे पुरा परिवर्तन आना शुरू हुआ. २०१४ मे सार्क के सभी राष्ट्रों के प्रमुखो को शपथविधी समारोह मे आमंत्रित कर दक्षिण आशिया के मुखिया के रूप मे अब भारत की नयी सरकार पहल करेगी यह दिखाने का प्रयास किया गया और वह यशस्वी बह भी रहा. दुसरा, विश्वभर मे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान के अलग अलग गौरे राजनीतिक रिश्तो को अधिक दृढ करने के लिये उठाया कदम था. तिसरा, वैश्विक राजनीति का संपर्क सचिवस्तरो से हटाकर मंत्रीस्तर लाकर उनके माध्यम से संबंधो पर भर दिया गया. चौथा, पारंपारिक संगठण सार्क, बिमस्टेक, ब्रिक्स, नाम को कमजोर अमरिका के साथ प्राधान्यवाले रिश्तो पर बल दिया गया. जिसमे चीन के विस्तारवाद पर अमरिका जैसे प्रभुत्व शाली राष्ट्रों का सहयोग मिल सके. पाचवा, नयी विदेशनीति मोदी नाम की हो और पारंपारिक 'नेहरूयन' नीति से मुक्त हो इस तंत्र का निर्माण करना.

२०१४ से २०२० तक नरेंद्र मोदी ने विश्व के १२० देशो मे जाकर भारत की नयी छबी निर्माण करते हुए अलग अलग करार भी किये और निवेश को बढ़ावा दिया साथ मे फ्रान्स, रशिया, इस्त्रायल, स्वीडन, अमरिका से लष्करी शस्त्रसामग्री प्राप्त कर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करने की अपनी दृष्टी रखी. कोव्दिड काल मे विश्व मे जो परिस्थितीया निर्माण हुयी उसका फायदा उठाते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान अधिक दृढ करने की कोशिश की. एक तरफ संगठण को कमजोर किया गया तो दुसरी तरफ पर प्रभावी लस का उत्पाद कर सार्क देशो को सहायता मुहय्या करवायी. मालदीव, बांग्लादेश, भूतान, अफगाणिस्थान को अलग अलग वैद्यकीय सहायता दी गयी. 'बंदे भारत मिशन' अंतर्गत पूरे विश्व मे जहा भारतीय प्रवासी अटके थे उन्हे वापस लाया गया संख्या पाच लाख से भी ज्यादा थी. इस्त्रायल-पॅलेस्टिनी विवाद पर समझौते की बात करते हुये पॅलेस्टाईन को खुला समर्थन दिया तो दुसरी तरफ बेंजामिन नेत्यानाहू को हमदर्दी दिखायी. अफगाणिस्तान मे लोकतांत्रिक सरकार समाप्त हो कर तालिबानी राजवट का निर्माण हुआ वहा से शिख, हिंदू एंवम भारत से हमदर्दी रखने वाले अफगाणी लोगो को सुरक्षित लाने का मिशन पुरा किया गया. युकेन से लक्षायधी छात्रों को 'गंगा मिशन' के अंतर्गत सुरक्षित वापस लाया गया. इसी दौरान भारत ने 'लूक ईस्ट' पहलीसी बदल कर 'लुक वेस्ट, अक्ट ईस्ट' नीति को उभरकर सामने आयी. चीन के विस्तारवाद पर निर्यंत्रण आणि हेतु क्याड नामक संगठण मे भारत ने हिस्सेदारी की.

एक मायने मे देखे तो कोव्दिड के पछात ही नहीं तो नरेंद्र मोदी की सरकार २०१४ मे सत्ता मे आने के बाद उन्होंने अपने नये विश्वनीति को आकार दिया जिसमे राष्ट्रीय स्तर पर अलग नीति एंवम

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग नीति इस धारणा को अंगल लाया. प्रजासत्ताक भारत की विदेशनीति को समाप्त कर स्वतंत्र ऊर्जावान नीति को जन्म दिया. इस्त्रायल के साथ खुले संबंध तथा बड़े या छोटे वाले राष्ट्रों के अंदरूनी राजनीति में सक्रियता दिखाने शुरू हुई. अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन इस का उदाहरण है.

भारत ने अपनी बदलती वैश्विक राजनीति में जिन मुद्दों का प्रभाव छोड़ा है उसमें मुगल स्वराज के नेतृत्व में येमन का 'राहत मिशन' जिसमें अमेरिका सहित अन्य 36 राष्ट्र के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. अमेरिका और सभी देशों इस कृती पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया था. सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यत्व के लिए अन्य देशों का सक्रिय समर्थन मिलना तथा एनएसजी में प्रवेश हेतु सहयोग की शिकस्त इस बात को हम अगर समझे तो भारत की नयी विदेशनीति समझ आ जाती है. पटाणक्रोट, बालाक्रोट के बाद पाकिस्तान में किये गये सर्जिकल स्ट्राइक पर चीन व अन्य देशों का विरोध न जताना आतंकवाद के खिलाफ लड़ी गई कूटनीतिक यशस्विता मानी जाती है. विश्व के बड़े तिनो राष्ट्र के साथ वर्तमान समय में भारत का जो दृष्टिकोण रहा है शायद उससे कुछ बातें कल भारत के लिए लाभप्रद रहेंगी यह मान नहीं सकते. यूपीए प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में अमेरिका के साथ जो सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित हुये थे वह वर्तमान समय में मैत्रीपूर्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुरिया बनती जा रही है. रशिया का पाकिस्तान के तरफ झुकाव, दक्षिण आशिया-पूर्व आशिया में चीन की सक्रियता यह भारत को अलग-थलग रखने की आंतर्राष्ट्रीय नीति को समझना वर्तमान में ज्यादा महेफूस होगा.

उपसंहार

कोव्हिड के पश्चात बदलती वैश्विक राजनीति भूराजकीय मानचित्र में बदलाव लाने की संभावना है. इस्त्रायल-गाझापट्टी, अफगानिस्तान, युक्रेन इसके उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं. वर्तमान में लोकतंत्रिक व्यवस्था हो या अधिनायकवादी तंत्र वह नाज़ी सिद्धांत का अनुकरण करते दिखाई दे रहा है. नाज़ीवाद के दो सिद्धांत हैं एक, अल्पसंख्यांक (चाहे वह रंग, धर्म, जात, भाषा, वंश) समूह को निशाणा बनाकर उन्हें अपने देश के बाहर करता है और दुसरा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की हिमायत करता है. शुमैन कहते हैं 'साम्राज्यवादी चाहे जितनी नैतिकता की बातें करे और दुसरे बहाने साम्राज्यवाद, अधिन जातीयों पर शक्ति और हिंसा द्वारा थोपा गया विदेशी शासन है'.⁴ युक्रेन पर रशिया का आक्रमण तथा इस्त्रायल, स्वीडन, नार्वे देश का अल्पसंख्यांक समुदाय प्रति रवय्या यह बात सुनिश्चित करता है. वर्तमान वैश्विक राजनीति सौदेबाजी कि सिद्धांत पर आधारित है. थामस शिलींग ने अपने मत को रखते हुये कहा था कि 'खुले युद्ध से ही इसका अर्थबोध हो सकता है'⁵ यह सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादा प्रचारित हुआ. रशिया युक्रेन विवाद में यही स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है. रशियाने स्पष्ट किया कि युद्ध तभी थम सकता है जब युक्रेन नाटो की सदस्यता से बाहर होता है और आश्वस्त करे की युक्रेन में युरोपियन महासंघ या नाटो की उपस्थिति नहीं होगी. अगर युक्रेन पुरे तबाही के बाद मानता है तो रशिया के विस्तारवाद को और बढ़ावा मिलेगा. वैश्विक राजनीति १९४५ से लेकर १९९१ तक द्विधृवीय थी. १९९१ से २००१ में एकधृवीय बनी. २००१ से २०१६ तक बहुधृवीय रही. २०१६ से वह त्रीधृवीय शृंखला में तब्दील हो चुकी है. जिसमें विचारधारा शून्यतम अवस्था में है और बाजारवाद तथा शस्त्रो-अस्त्रो पर उसकी रचना दिखाई देती है. जिसका एक अक्ष अमेरिका है, दुसरा चीन, तो तिसरा रशिया है. रशिया को लगातार मिलता समर्थन उसके स्थान की मजबूती को दर्शाता है. भारत इस शृंखला में नहीं है. सत्ताधारी राजनीतिक गलीयारे उनके मातृ-पितृ संगठन इस संदर्भ में कुछ कहते हैं, तो वह आभासी है. वो संदर्भ को देखना चाहिए पहले आर्थिक

एवं लष्करी तौर पर, दुसरा आपके पडोशी रिश्ते। ये दोनो बाते वैश्विक राजनीति में अपनी ताकत को दर्शाने वाले है. चीन और भारत में जीडीपी की तुलना हो सकती लेकिन उससे वास्तविकता बदल नहीं जाती. चीन २१ ट्रिलियन डॉलर्स के साथ खड़ा तो है साथ में १५८ देशों को उत्पाद निर्यात करके हर साल दस अर्ब डॉलर्स का व्यवसाय करता है. तुलना में भारत पिछड़ा है. वैश्विक राजनीति का मापदंड लष्करी सामग्री पर भी तय होता है. भारत ने पिछले पाच साल में लष्करी क्षेत्र में तीन लक्ष सैनिकों की जगह रिक्त कर दी. आर्थिक अस्त्रों और मित्रता वाले देशों में हम पीछड़े हैं. जपान एवं इस्त्रायल दीर्घकालीन मित्र तर्फी बन सकते हैं जब हम उन्मादी राष्ट्रवाद को छोड़कर विकासवाद की बात करें. राष्ट्रवाद-विकासवाद एक साथ चल नहीं सकते. प्रारंभिक दौर में वह अच्छा लगता है, लेकिन दिर्घस्तर पर वह अनुपयुक्त रहेगा. कद्दावर नेता यह विदेश नीति की पहचान नहीं हो सकती. रशिया-युक्रेन संघर्ष में यूनो में तीन बार भारत ने खुद को तीन बार तटस्थ रखा यह नेहरूयन परंपरा की जरूरत को दर्शाता है. हमने वर्तमान समय में जो संगठन को कमजोर किया उसे दोबारा पुनर्जीवित करने की जरूरत है. अर्थव्यवस्था के साथसाथ समाजव्यवस्था की एकात्मता वर्तमान समस्या का हल भी हो सकता है. कोविड के पश्चात जर्मनी, चीन इनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर नहीं बनीं. आनेवाले वर्षों में जर्मनी और एक बार युरोप पर हावी होगा इसी कारण जर्मनीने रशिया के खिलाफ लामाबंदी करने के खिलाफ अपना मत नहीं दिया. इराण, तुर्कस्तान रशिया के साथ में है, इराक, अफगाणिस्तान की भूमिका भी रशिया को लाभान्वित करने वाली है इस पृष्ठभूमिपर विश्व का त्रिस्तर विभाजन सत्ता संतुलन एवं मानवी व्यवस्था के समक्ष एक बड़ा गहरा आव्हान है. अच्युत गोडबोले अपनी 'अर्थात' नामक सुप्रसिद्ध किताब में लिखते हैं 'साम्राज्यवाद, विस्तारवाद का गणित रखने के बजाय विश्वभर में भुखे, प्यासे, दरिद्री लोगों को उनकी जरूरतें पूरी करने की हिमायत दे यह नीति होनी चाहिए'⁹ न की विश्वयुद्ध की?

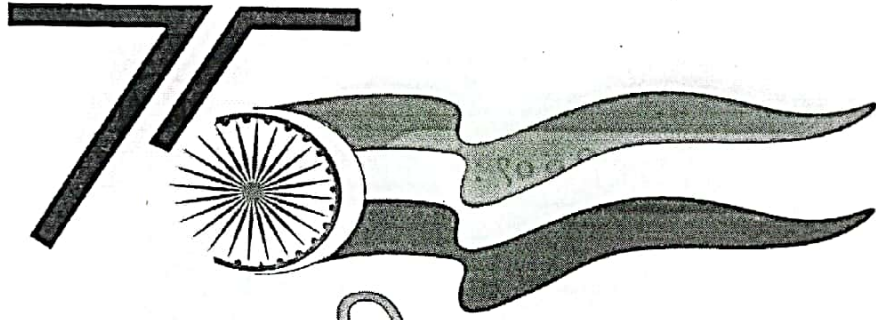
संदर्भ ग्रंथ :

१. आंतरराष्ट्रीय संबंध, डॉ. वसंतराव रायपूरकर, श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर २००६, पृष्ठ. क्रं ५-६
२. आंतरराष्ट्रीय संबंध, डॉ. बी. डी. तोडकर, प्रशांत प्रकाशन, जलगाव, २०१७, पृष्ठ. क्रं. ३३
३. भारतीय विदेशनीति, जे. एन. दीक्षित, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, २००१, पृष्ठ. क्रं. ३२३
४. मोदी पर्व, श्रीराम पवार, सकाळ प्रकाशन, पुणे, २०१६, पृष्ठ. क्रं. १७२
५. अंतरराष्ट्रीय संबंध, डॉ. एस. सी. सिंहल, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आग्रा, २०१३ पृ. क्रं. १३२
६. आंतरराष्ट्रीय राजकारण डॉ. बी. डी. तोडकर, प्रशांत पब्लिकेशन जळगाव, २०२०, पृष्ठ क्रं ६६
७. अर्थात, अच्युत गोडबोले, राजहंस प्रकाशन, पुणे, २०१३, पृष्ठ. क्रं. ४३०

UGC CARE LISTED
ISSN No.2394-5990

संशोधक

• वर्ष : ९० • डिसेंबर २०२२ • पुरवणी विशेषांक ०७



आज़ादी का
अमृत महोत्सव



इतिहासकार्य वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे

Scanned with CamScanner



विचारांतील स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर करण्यासाठी शाश्वत विकासाची संकल्पना विकसित होणे खूप गरजेचे आहे.

शाश्वत विकासाची सद्यस्थिती :

शाश्वत विकास आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत दोन्ही संकल्पना एकत्रित विचार केला जातो. भारतामध्ये १९७२ साली पर्यावरण नियोजन व समन्वय राष्ट्रीय परिषद NCEAP तसेच एकत्रित या प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी १९८५ मध्ये भारत सरकारने स्वतंत्र पर्यावरण व वने मंत्रालय सुरू केले. याच अनुषंगाने प्रत्येक घटक राज्याचे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण विभाग स्थापन करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये सेंटर फॉर सायन्स अँड इनव्हायर्स नई दिल्ली, सेंटर फॉर इनव्हायर्स एज्युकेशन, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी इत्यादी संस्थामधून प्रयत्न केले जात आहे. शासकीय प्रयत्नांबरोबरच अशासकीय संघटनांनी सुद्धा अनेक प्रयत्न यामध्ये केलेले आहे. ज्यामध्ये आगाखान ग्रामीण मदत कार्यक्रम, विज्रम साराभाई विकास व अन्न प्रक्रिया केंद्र आणि भारतीय उद्योग प्रतिष्ठान सारख्या अशासकीय संघटनांनी शाश्वत विकासासाठी खालील काही महत्त्वाची उदाहरणे व प्रयत्न केलेल्या आपल्याला दिसून येते.

चिपको आंदोलन हे भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण घटना आहे. सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली वृक्षतोडी विरुद्ध केलेले फार मोठे आंदोलन होते. राळेगण सिद्धी श्री अण्णा हजारे यांनी ग्रामस्थांच्या सामुदायिक सहभागातून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाती घेतला. जलसंधारण जमिनीचे वापर करून त्यांनी सिंचन क्षेत्रात वाढ करून संपूर्ण गावांचा कायापालट केला. शाश्वत विकासाचे अनुकरणीय व आदर्श म्हणून हा नमुना आहे. सामुदायिक प्रयत्नांतून शाश्वत विकास ओ पर्यावरणाचे संरक्षण कसे साधता येते याचे उत्तम उदाहरण घायचे असेल तर राजस्थान मधील अलवार जिल्ह्यातील भाऊता कोलल्या नावाचे खेडे आहेत दहा वर्षात सामुदायिक भूमिकेतून राजेंद्र सिंग यांनी २५ विहिरी, तलाव, बांधारे आदींची निर्मिती करून वाळवंट असलेल्या गावाला आज नंदनवनाचे स्वरूप तरी प्राप्त करून दिलेले आहे. हे घडले ते सामुदायिक भूमिकेतून झालेले आहे. केरळ शास्त्र-साहित्य परिषद १९६७ या परिषदेने सदाहरित वर्षा घनातील वनस्पतींना अच्छा दिलेल्या घनाचे संरक्षण करण्यासाठी मोठे आंदोलन उभे केले आहे. मध्य प्रदेशातील हॉर्गिगाबाद येथील एक लाख शेतकऱ्यांनी १९७७ साली नर्मदा नदीची उपनदी देवना या तवा या नद्यांच्या संगमावर उभारल्या जाणाऱ्या धरणाविरुद्ध मिट्टी बचाव अभियान पुढे

केलेले आहे. श्रीमती मेधा पाटकर यांनी नर्मदा बचाव अभियानात गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालवले जात आहेत. गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातील मोठे वनक्षेत्र सरदार सगेवराच्या पाण्याखाली जाणार आहेत, त्यामुळे पर्यावरणाची अवनती होणार आहे, ते टाळण्यासाठीच आंदोलन चालू आहेत. टेहरार बांध विरोधी संघर्ष (उत्तराखंड) समितीची स्थापना १९७८ मध्ये व्ही. डी. सकलानी यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. आणि या धरणाचे बांधकाम भूकंप प्रवण क्षेत्रात होत असल्याने या समितीने विरोध केलेला आहे.

वरील उदाहरणावरून आपल्याला असे दिसून येते की, भारतातील शाश्वत विकासासाठी अनेक स्तरावरून प्रयत्न केले गेलेत. परंतु त्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीची जाणीव जागृतीची व सामुदायिक निर्मितीची गरज होती. सर्व समाज घटकांनी उद्योग-व्यवसायकानी हा विचार करण्याची गरज आहे. आजच्या नैसर्गिक संरक्षणावर उद्याच्या पिढीचे भवितव्य अवलंबून आहे. म्हणून निसर्ग संवर्धनाच्या पुरेसा प्रचार आणि प्रसार करण्याची आज गरज आहे.

मानवांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून रासायनिक खते औषधांचा अती उपयोग करून कृषी योग्य जमिनीची प्रत प्रतिवर्षी कमी होत आहे. पाण्याचा अतिवापर करून जमीन खरपट होत आहेत. मोठ्या शहराजवळील कृषी योग्य जमिनीचा उपयोग सिमेंटच्या जंगलाकरिता होत आहे. भारताच्या आर्थिक विकासात शेती महत्त्वाचा घटक आहे. काही भागात अनेक घटकांवर प्रदूषण वाढत आहेत म्हणून आर्थिक विकास आणि पर्यावरण यांचा समन्वय साधून शाश्वत विकास करणे गरजेचे आहे. कारण सर्वसमावेशक विकास हवा असेल तर त्या शेतीचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करावेच लागतील.

शाश्वत विकासाचा पुढील आव्हाने :

आजच्या काळात सर्व देशांच्या व सर्व मानवजातीचा सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक असल्यामुळे वरील काही संस्था व संघटना शाश्वत विकास या पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करीत आहेत. तथापी हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत शाश्वत विकासाचा विचार पुढे नेण्यामध्ये काही अडचणी व आव्हाने अवरोध म्हणून उभी राहिलेली दिसून येते. ती पुढील प्रमाणे आपल्याला दिसून येतात.

घाबती लोकसंख्या व दारिद्र्य निर्मुलनाचे आव्हान, जलप्रदूषण दूषित पाण्यामुळे दरवर्षी जवळपास पाच ५ वर्षांखालील १५ लक्ष मुले मरतात तर २० कोटी माणसांच्या कामाचे ताम वाया जातात. मुंबई, सारख्या महानगरत पुत्रजन्म



भारतातील पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शाश्वत विकासापुढील आव्हाने

डॉ. संदीप तुंडूरवार

सहयोगी प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

श्री बिज्ञाणी नगर महाविद्यालय नागपूर

मो. क्र. ९८९०२७५७९३

Email: smtundurwar@yahoo.in

श्री. भास्कर वघाळे

राज्यशास्त्र विभाग

श्री बिज्ञाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

मो. क्र. ७२७६६३३७९०

Email : Bhaskar99waghale@gmail.com

सारांश :

सुरुवातीच्या काळात नैसर्गिक साधन सामुग्रीची विपुलता होती. काळानुसार होणार्या लोकसंखेचा विस्फोट आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती याचबरोबर मनुष्यांचा उपभोग घेण्याचा स्तरही उंचावत गेला. इतकेच नव्हे तर सर्वसामान्य जीवनामध्ये कृत्रिम साधनांचे प्रयोग इतके वाढले की त्यामुळे निसर्ग दूषित होऊ लागला. निसर्गापासून मनुष्य दूर जाऊ लागला. आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्याचा धावपळीत पर्यावरणाचा विनाशाकडे मनुष्याने पावले टाकली. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मनुष्याचे दुर्लक्ष झाले आणि उत्पादन वाढीच्या मोहापुढे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अफाट प्रमाणात वापर केला गेला. त्यातूनच निसर्गाचा अवनतीला सुरुवात झाली. सध्या या स्थितीची धोक्याची घंटा वाजत आहेत म्हणूनच शाश्वत विकासाची संकल्पना पर्यावरणाच्या संरक्षणाशिवाय करणे अशक्य आहे. म्हणून मनुष्य आणि निसर्गाचे तुटलेले संबंध पुन्हा जोडणे. मनुष्याच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनाला पर्यावरणप्रीय आणि विनयशील व विवेकशील बनविणे आवश्यक झाले आहे. असे व्यापक व सर्वांच्या हिताचा विचार करून विकासाचा गाढा पुढे नेण्याची गरज आहे. हा विचार भारतामध्ये सामूहिक भावनेतून बिंबवणारे माननीय अण्णा हजारे यांच्या राळेगणसिद्धी व देवजी तोफा यांचा मॅट्टा (लेखा) या गावांचा झालेला शाश्वत विकास हे सामुदायिक विकासाचे उत्तम उदाहरण आहेत. या दोन उदाहरणांच्या अनुकरण संपूर्ण देशाने करणे आवश्यक आहेत. एवढेच नाही तर अशी काळाची गरज सुद्धा आहे. त्यासाठी लोकसंख्येवर नियंत्रण निसर्गातील छोट्या-छोट्या वस्तूतील गुणांची ओळख, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, याचबरोबर मनुष्याला निसर्गाबरोबर जगण्याची अभिलाषा निर्माण करणे हे गरजेचे आहे. सदर संशोधन पेपरमध्ये पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून शाश्वत विकास करत साध्य होऊ शकतो यावर चर्चा करण्यात आली आहे.

विज्ञाशब्द: पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास, पर्यावरणाची अवनती

प्रस्तावना :

आधुनिक जागतिक व्यवस्थेमध्ये पर्यावरणीय सुरक्षा आणि शाश्वत विकासाचा विचार केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला आहेत. मानवी जातीचा शांततापूर्ण आणि सर्वांगीण शाश्वत आणि टिकाऊ विकासासाठी पर्यावरण संरक्षणाची अत्यंत गरज आहे. शाश्वत विकास ही बहुआयामी व परस्परवलंबी संकल्पना आहे. या संकल्पनेत वर्तमान काळातील पिढीबरोबरच भविष्य काळातील पिढीचा सुद्धा विचार केला जातो. ही संकल्पना नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विवेकबुद्धीने व दूरदृष्टीने वापर करण्यास अधिक भर देते. परंतु सध्या होत असलेला विकास कुणाच्यातरी विनाशावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे तो विकास तात्पुरता किंवा अल्पजीवी स्वरूपाचा आहेत. हल्लीच्या काळात निर्माण झालेला ऊर्जानिर्मितीचा प्रश्न आणि वीजनिर्मिती करिता लागणारा दगडी कोळसाची टंचाई ही शाश्वत विकासाला अवरोध ठरलेली दिसून येते. विकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे असा सतत चालणारा विकास साधत असताना मानवाने नैसर्गिक संपत्तीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला आहे. मानव व पर्यावरण यांचा अतूट संबंध असल्यामुळे पर्यावरण घटकातून आर्थिक विकास होत गेला. पर्यावरण संरक्षण व मानवी जीवन एकमेकांना पूरक आहेत याची जाणीव होऊन शाश्वत विकासाची संकल्पना पर्यावरण संरक्षण दृष्टिकोनातून स्पष्ट करण्यात आली. जो विकास मानवाच्या सध्याचा व भविष्यकालीन संतुलित पूर्ती करतो तो विकास म्हणजे शाश्वत विकास होय.

शाश्वत विकासाची संकल्पना पर्यावरणाला महत्त्व देणारी आहे. त्यामध्ये मानवी गरजा, आर्थिक वाढीचे एकात्मिक पर्यावरणीय आरोग्य व निरंतर आर्थिक विकास केंद्रस्थानी असतो. पर्यावरण व विकास आयोगाद्वारे १९८७ पासून शाश्वत विकासाचा संकल्पनेचा उगम होऊन पर्यावरण संरक्षणातील त्याचा विकास होत आहे. शाश्वत विकासासाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीची हानी व भावी पिढ्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी निसर्गाला कोणताही धक्का न लावता लोकांच्या आजच्या गरजा पूर्ण केल्या जातात व आर्थिक विकास साधला जातो. पर्यावरणाचा होणारा न्हास

अनुक्रमणिका

१. डिजिटल युगात ग्रंथालय सेवांचा प्रचार करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर
- आशीष ठाणेकर ----- ७
२. हितं मनोहारी च दुर्लभम् ।
- डॉ. अबोली व्यास ----- ११
३. कृषी अर्थव्यवस्थेवर गांधी विचारांची प्रासंगिकता - एक आर्थिक सिंहावलोकन
- प्रा. बोधे श्रीकृष्ण बी ----- १५
४. संजय गांधी निराधार योजनेचे ग्रामीण विकासात योगदान
- प्रा.डॉ. राजेश प्रल्हाद कांबळे, प्रा.मनिषा दर्शन बारसागडे ----- १९
५. गांधीचा ग्रामीण भारत, स्वःशासन, आणि ग्रामीण शाश्वत विकास
- डॉ. नितीन सुरेशराव कायरकर, डॉ. सचिन पत्रूजी भोंगेकर ----- २२
६. जिल्हा उद्योग केन्द्राचे कार्य व भूमिका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
- डॉ. महेन्द्र पांडुरंगजी गावंडे ----- २५
७. भारतीय लोकशाही पुढील नवीन आव्हाने (एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवलोकन)
- सहा. प्रा. डॉ. रवी एस. सोरते ----- ३०
८. स्वातंत्र्यपूर्व भारतीय वाहतूक व्यवस्थेत रस्त्याचा विकास
- डॉ. देवीदास ग्यानोजी गाडेकर ----- ३६
९. बाल मजूर व मानवाधिकाराची उपेक्षा
- डॉ. मंजूषा राजेंद्र ठाकरे ----- ४१
१०. शांता शेळके यांचे भावगीत : एक चिंतन
- डॉ. नरेंद्र ईश्वर घरत ----- ४५
११. दलित आत्मकथने: मराठी साहित्यातील महत्त्वाचा वाङ्मयीन आविष्कार
- डॉ. पराग मुरलीधर सपाटे ----- ५०
१२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा - सद्यस्थितीचे विश्लेषण (जागतिक उपासमारी निर्देशांक २०२२ च्या संदर्भात)
- डॉ. पंकज तायडे ----- ५४
- ✓ १३. भारतातील पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शाश्वत विकासापुढील आव्हाने
- डॉ. संदीप तुंडूरवार, श्री. भास्कर बघाळे ----- ५९



४३. तथागत गौतम बुद्धाचे अर्थशास्त्र
- डॉ. सिद्धार्थ हरिदास भेथ्राभ १९१
४४. राज्यपुनर्रचना आयोग आणि विदर्भ
- डॉ. शरद सांबारे, डॉ. रायन महाजन १९६
४५. महिला विकासाच्या घाटचालीमध्ये फायदयांची मदत
- सारंगा किसन गेडाम २०१
४६. भारतीय अर्थव्यवस्था व डिजिटल मुद्रा- एक आर्थिक विवेचन
- प्रा.सतीश आर.जाधव २०५
४७. वसाहतोत्तर भारतातील गोंडवाना चळवळ
- प्रा.डॉ. सतीश रामदास महळे २०९
४८. गोरबंजारा समाजावरील शहरीकरणाचा प्रभाव: महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भात
- प्रा. सतिश बं. राठोड २१३
४९. गडचिरोली जिल्ह्यातील रमाई आवास योजनेचा आढावा
- सतिश शामराव खोब्रागडे, प्रा. डॉ. राजेश प्रल्हाद कांबळे २१७
५०. राष्ट्रीयकरणानंतर भारतीय बँकांची प्रवृत्ती एक अभ्यास
- डॉ. शंकर मारोती सावंत २२०
५१. महाविद्यालयीन मुलांच्या शारीरिक बदलांवर कपालभातीचा होणाऱ्या परिणामाचे अध्ययन
- डॉ.सुभाष एस. दाढे २२५
५२. आभासी चलन आणि भारतातील सद्यस्थिती
- डॉ. सुरेखा भिंगारदिवे २३०
५३. कोविड-१९ चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम
- प्रा. डॉ. टी. एम. गुरनुले २३३
५४. माडिया आदिवासीचे उद्धारक - डॉ.प्रकाश बाबा आमटे
- प्रा.संजय उत्तमराव उगेमुगे, डॉ. प्रकाश.आर. शेंडे २३८
५५. मराठी साहित्यात अनुस्यूत मानवतावादी मूल्ये : एक परीक्षण
- प्रा.डॉ. विजय रुपराव राऊत २४२
५६. खान्देशातील कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी
- डॉ.विनोद आत्माराम नन्नवरे २४६
५७. भारताच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची समिक्षा
- डॉ. विठ्ठल घिनमिने २५०



२८. १९९० नंतर महाराष्ट्रातील राजकारणाचे बदलते प्रवाह - एक राजकीय सिंहायलोकन
- डॉ. एन. डी. बालपांडे ----- १२४
२९. नोकरी करणा-या स्त्रियांमध्ये स्तनांच्या कर्करोगाविषयीची जाणूकता
- प्रा. विभावरी केवलराम नखाते, प्रा. डॉ. उषा खंडाळे ----- १२९
३०. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारिद्र्य निर्मुलनाकरीता पायाभूत सुविधेची आवश्यकता
- निलेश अरूण दूर्गे, प्रा. डॉ. प्रकाश बी. तितरे ----- १३१
३१. मोडी लिपीचिन्हांचे स्वरूप आणि देवनागरी लिपीचा त्यावरील प्रभाव
- डॉ. निलेश एकनाथराव लोंढे ----- १३७
३२. भारत अमेरिका संबंधातील नवीन प्रवाहाचा उदय
- सहा. प्राध्या. पवन महंत ----- १४१
३३. उदाजी चैव्हाण व्यक्ती आणि कर्तृत्व (इ.स. १६९२-१७६२)
- प्रा.डॉ.प्रज्ञा भा. कामडी ----- १४७
३४. महान शूर सेनापती, संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव यांचे मोगल- मराठा संघर्षातील
-ऐतिहासिक विश्लेषण
- प्रा.प्रमोदिनी ज्ञा. खोरगडे (सातंगे) ----- १५१
३५. ग्रामीण कथाकार -अशोक कौतिक कोळी
- प्रा.डॉ. प्रवीण घारपुरे ----- १५६
३६. भारतातील अनुसूचित जाती-जमातींसाठी घटनात्मक तरतुदी
- प्रा. डॉ. विश्वनाथ आत्माराम देकार ----- १६१
३७. जागतिकीकरण व भारतीय उच्च शिक्षण
- प्रा.डॉ. राजेश प्रल्हाद कांबळे ----- १६५
३८. प्राचीन मराठीतील संतकवींची साहित्यदृष्टी
- प्रा. डॉ. राकेश कभे ----- १६८
३९. आधुनिक मराठी कवयित्री
- डॉ. राखी जाधव ----- १७३
४०. ग्रामीण भागातील शालेय बालकांच्या वजन व उंचीचे प्रमाणित मापानुसार तुलनात्मक अध्ययन
- सौ. मेघा मोहन रतकंठीयार, डॉ. माधुरी नामदेव कोकोडे ----- १७७
४१. शंकरराय खरात-यांचे 'तराळ-अंतराळ' या आत्मचरित्राचे प्रगल्भ स्वरूप
- प्रा. डॉ. रिता द. घाळके (डंभाळे)----- १८१
४२. घाटल्या नागरीकरणाचा अभ्यास (संघर्ष : जळगाव शहर)
- डॉ. सचिन भास्कर चुंभार ----- १८५



१४. भारत सासणे यांच्या दीर्घकथा साहित्यातील समूहनिष्ठा
- डॉ. अशोक भक्ते ----- ६३
१५. स्त्री-पुरुष असमानता - एक लिंगभेद व विविध दृष्टिकोन
- डॉ. चंद्रशेखर आर. भेजे ----- ६८
१६. महाराष्ट्रातील भिल्ल आदिवासी जमातींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास
- डॉ. गणेश एन. बहादे ----- ७२
१७. घनकचरा प्रदूषण - कारणे, परिणाम व उपाय
- प्रा. डॉ. जया एस. सवाईथूल ----- ७६
१८. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदेतील कार्य आणि महारेतरांची भूमिका
- डॉ. सूर्यकांत महादेवराव कापशीकर ----- ८२
१९. गडचिरोली जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सन २०२२ मध्ये उच्च व्यावसायिक व
तांत्रिक शिक्षणाच्या उपलब्धतेचा मागोवा
- प्रा. डॉ. राजेश पी कांबळे, श्री किशोर नुकुंद्र बागडे ----- ८७
२०. पूर्व नागपूरातील जेष्ठ नागरीकांची कौटुंबिक व सामाजिक अभिरूची: एक अध्ययन
- डॉ. क्षमा डी. चव्हाण ----- ९०
२१. रामचंद्र गणेश कानडे आणि हैदरअली : एक ऐतिहासिक अध्ययन
- डॉ. चंद्रशेखर तु. क्षीरसागर ----- ९७
२२. जागतिक महामारीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा
- डॉ. लिलाधर खरपुरिये ----- १००
२३. भारतीय राष्ट्रादाच्या उदयात महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांचे योगदान : ऐतिहासिक अध्ययन
- डॉ. माधुरी प्र. पाटील ----- १०३
२४. रा. रं. चोराडे यांचे ग्रामीण जीवनाला अधोरेखित करणारे कादंबरी लेखन
- डॉ. महेश बी. जोगी ----- १०७
२५. रमाई आवास योजनेतील लाभाऱ्यांच्या सामाजिक स्थितीचे अध्ययन
- डॉ. राजेश पी कांबळे, प्रा. माया ई. डकाहा ----- १११
२६. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी लोक घेत असलेले अन्नपदार्थ व त्यातील पोषक घटक
आणि औषधी गुणधर्म
- मिनाक्षी दादाजी नागदेवते, डॉ. माधुरी ना. कोकोडे ----- ११४
२७. ग्रामिण विद्युतीकरणात यशंतराय नाईक यांचे योगदान
- प्रा. डॉ. मोतीराज रामदास चव्हाण ----- १२०



५८. बुध्द तत्वज्ञान जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग
- प्रा.डॉ. वामन ए. खोब्रागडे ----- २५५
५९. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि भाऊसाहेब पंजाबराय देशमुख यांच्या कार्यातील समन्वय
- प्रा.डॉ.वासूदेव वा. भगत ----- २६०
६०. मोघल कालीन स्त्रियों की सामाजिक, राजकीय स्थिती
- डॉ. देवीदास गाडेकर ----- २६५
६१. प्रादेशिक इतिहास: इतिहास लेखन का नया प्रवाह
- प्रा. (डॉ.) शामराव कोरेटी ----- २६८
६२. खेल के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की आवश्यकता
- Dr. Manojkumar Varma ----- २७१
६३. राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के आयाम
- डॉ. जितेंद्र सावजी तागडे ----- २७५
६४. रघुवीर सहाय - कोठरी की कैद: उपन्यास में जीवनमूल्य
- डॉ. मीनाक्षी सोनवणे ----- २७९
६५. तलाक के संबंध में इस्लाम का दृष्टिकोण
- नफीसा अब्दुल सादिक ----- २८१
६६. मानसिक स्थिती एवं व्यक्तित्व का खेल पर प्रभाव- एक अवलोकन
- डॉ. प्रा. वसंत निनावे ----- २८३
६७. जलकुंभी : ग्रामीण अर्थव्यवस्था परपारिस्थितिक प्रभाव तथा संभावनाए
- प्रो.डॉ.राधारु.सवजियाणी ----- २८६
६८. भारत-चीन संबंधों की समकालीन प्रकृति - एक राजनीतिक समीक्षा
- प्रा.राजेंद्र घोरपडे ----- २९०
६९. भारत में झुग्गी-झोपड़ी के निवासी: दैनिक आवश्यकता को पूरा करना एक चुनौती
- डॉ. राजेश्वर दिनकर रहांगडाले ----- २९३
७०. आधुनिक हिन्दी उपन्यासों में धार्मिक सांप्रदायिकता का चित्रण
- डॉ. विकास विठ्ठलराय कामड़ी ----- २९७





UGC CARE LISTED
ISSN No. 2394-5999

इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे मंडळ, धुळे
या संस्थेचे त्रैमासिक

॥ संशोधक ॥

पुरवणी अंक ७ - डिसेंबर २०२२ (त्रैमासिक)

- शके १९४४
- वर्ष : ९०
- पुरवणी अंक : ७

संपादक मंडळ

- प्राचार्य डॉ. सर्जेराव भामरे
- प्रा. डॉ. मृदुला वर्मा
- प्रा. श्रीपाद नांदेडकर

अतिथी संपादक

- डॉ. गिझाला हाशमी
- डॉ. सिद्धार्थ हरिदास मेश्राम
- प्रो. मोहम्मद अस्सरा

* प्रकाशक *

श्री. संजय मुंदडा

कार्याध्यक्ष, इ. वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे ४२४००१
दूरध्वनी (०२५६२) २३३८४८, ९४०४५७७०२०

कार्यालयीन वेळ

सकाळी ९.३० ते १.००, सायंकाळी ४.३० ते ८.०० (रविवारी सुट्टी)

मूल्य रु. १००/-

वार्षिक वर्गणी रु. ५००/-, आजीव वर्गणी रु. ५०००/- (१४ वर्षे)

विशेष सूचना : संशोधक त्रैमासिकाची वर्गणी चेक/ड्राफ्टने
'संशोधक त्रैमासिक राजवाडे मंडळ, धुळे' या नावाने पाठवावी.

अक्षरजुळणी : सौ. सीमा शिंदे, वारजे-माळवाडी, पुणे ५८.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने या नियतकालिकेच्या प्रकाशनार्थ अनुदान दिले आहे. या नियतकालिकेतील लेखकांच्या विचारांशी मंडळ घ शासन सहमत असेलच असे नाही.



व शाश्वत विकासाची तत्त्व स्वीकारून नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संवर्धन करून जलद आर्थिक विकासाचा मार्ग स्वीकारणे या मुलभूत बाबीवर भर देणे ही काळाची गरज आहे.

उद्दिष्टे :

- १) पर्यावरण संरक्षणातून शाश्वत विकासाची भूमिका तपासणे.
- २) शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणाचे महत्त्व जाणून घेणे.

गृहीतक :

- १) पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शाश्वत विकासापुढे मोठे आव्हान उभे राहिलेले दिसून येते.
- २) पर्यावरणाचे संरक्षण केल्यास भविष्यातील विकासातील समस्या सोडविल्या जाऊ शकतात.

संशोधन पद्धती :

सदर संशोधन पेपरकरिता वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच दुय्यम सामुग्रीचा वापर केला असून यामध्ये संदर्भग्रंथ, शोधनिबंध, शोधप्रबंध मासिके व इंटरनेट वरील महितीचा वापर करण्यात आला आहे. राज्य व्यवस्थेकडून पर्यावरण संरक्षणाकरिता केलेल्या कायद्याचा यामध्ये आढावा घेण्यात आला आहे. सदर संशोधनापेपरमध्ये भारतातील पर्यावरणाच्या संरक्षणाकरिता निर्माण झालेल्या विविध चळवळीची चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच शाश्वत विकासाची संकल्पना आणि शाश्वत विकासाची आवश्यकता याबाबत सैद्धांतिक मांडणी करून भारतातील शाश्वत विकासाची सध्यास्थिती आणि विकासापुढील आव्हानाची चर्चा या पेपरमध्ये विश्लेषणात्मक पद्धतीचा आधारवर करण्यात आले आहे.

शाश्वत विकासाची संकल्पना :

मानव हा नैसर्गिक व सामाजिक पर्यावरणात जीवन जगत असतो. आर्थिक विकास आणि पर्यावरण यातील समन्वय साधणे आवश्यक असते, याच अनुषंगाने सन १९८७ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जागतिक आरोग्य संघटनेचे संचालक जी. एच. ब्रटलँड यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक पर्यावरण व विकास या आयोगाची स्थापना केली, त्यावेळी या आयोगाने शाश्वत विकासाची संकल्पना यिशाद केली. ब्रटलँड अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास की तो भविष्यकालीन पिढ्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या सामर्थ्याचे तडजोडी शिवाय वर्तमानकालीन गरजांची पूर्तता करणे होय. भावी पिढ्यांचा गरजा भागवण्याचा क्षमतेला कोणताही धोका न पत्करता लोकांचा वर्तमान गरजा

पूर्ण करणे म्हणजे शाश्वत विकास होय. याच संदर्भात रॉबर्ट अँलन असे म्हणतात की शाश्वत विक्राम असा विक्राम असतो की, मानवी गरजांची धिरकाळ टिकणारे माधन आणि मानवी जीवनाच्या दर्जात सुधारणा साध्य करणारा असतो. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेत उत्पादनात किती वाढ झाली याचा हिशोब करताना पर्यावरणाचा अवनतीचा खर्च वजा केल्यानंतर जो शुद्ध विकास त्याला शाश्वत विकास असे म्हणतात. निसर्गाचा साधनसामुग्रीचा, वहनक्षमता आणि पुनर्निर्माण क्षमता यावर शाश्वत विकास आधारित असतो.

आर्थिक विकास व पर्यावरणाचे नाते नवीन नाही ज्याप्रमाणे पर्यावरणाची अवनती व आर्थिक क्रिया यांच्यामधील उकल होत गेली त्याच प्रमाणे पर्यावरणाच्या माध्यमातून पूर्ण आर्थिक विकासावर भर दिला गेला. पर्यावरण संरक्षणाची मागणी आणि मानवी वंशाचे कल्याणकारी जीवन एकमेकांच्या विरोधात नाही तर एकमेकांना पूरक आहेत याची जाणीव होऊ लागली म्हणून ची रस्ताने विकासाची संकल्पना पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून प्रस्तुत करण्यात आली आहेत. पर्यावरण सहयोगी गटातून मानवाने या जीवनपद्धतीचा अंगिकार करून आर्थिक विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

शाश्वत विकासाची संकल्पनेचा उदय :

१९८७ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पर्यावरण आणि विकास आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग पृथ्वीवरील सामाजिक पर्यावरणीय समस्यांचे निरीक्षण करून त्यावर वास्तववादी उपाय योजण्यासाठी पेटीवर संसाधने पुढील पिढ्यांसाठी राखून त्यांच्या उपयोग चालू पिढ्यांसाठी शाश्वतरीत्या कसा करता येईल यावर उपाययोजना शोधण्यासाठी नेमण्यात आला होता. आणि आयोगाचे अध्यक्ष नार्वे या देशाचे पंतप्रधान होते.

शाश्वत विकासाची आवश्यकता :

विकास हा मानवाचा नैसर्गिक हक्क आहे या हक्काचा उपभोग घेताना नैसर्गिक साधनसामग्रीचा अमर्यादित वापर केला जातो. त्यातून पर्यावरणाची अवनती होते. त्यांच्या अनिष्ट परिणाम वर्तमान पिढीबरोबरच भविष्यातील पिढीवरही होत असतो. म्हणून विकासाच्या हक्का बरोबरच नैसर्गिक कर्तव्ये व जबाबदारीची जाणीव होणे गरजेचे असते. ही जाणीव करून देण्यासाठी शाश्वत विकासाची नितांत आवश्यकता आहे. भारताच्या संदर्भात विचार केल्यास दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी, पर्यावरणीय प्रदूषण फर्मी करण्यासाठी, जीवनशैलीचे प्रारूप बदलण्यासाठी, आरोग्याच्या गुणात्मक दर्जा सुधारण्यासाठी, निसर्गाबरोबरच जीवन जगण्यासाठी आणि महात्मा गांधींच्या